

बिल्डरों व प्रमोटरों की वेबसाइट पर नजर रखेगी आर्थिक अपराध इकाई

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाएं



बिल्डरों व प्रमोटरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर आर्थिक अपराध इकाई नजर रखेगी। ईओयू

बिल्डरों और प्रमोटरों की वेबसाइट पर नजर रखेगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। रैरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि थाना प्रभारियों को सभी

रैरा अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं से रैरा में निबंधित प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की अपील की, ताकि भविष्य में होने वाली किसी परेशानी से बचा जा सके। निबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी रैरा के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रैरा के अनुरोध पर अनिबंधित प्रोजेक्ट के निबंधन पर रोक लगा दी है। 30 सितंबर तक सभी बिल्डर और प्रमोटरों को वित्तीय वर्ष 2017-18 का ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

परियोजना स्थल पर साइन बोर्ड लगवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसपर रैरा में निबंधन संख्या समेत प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य है। अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए 631 आवेदन

आए हैं, जिसमें से मात्र 151 का निबंधन हुआ है। जांच के दौरान कई परियोजनाओं को शोकोज नोटिस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैरा सदस्य राजीव भूषण सिन्हा व सुबोध कुमार सिन्हा मौजूद थे।